पाठ्यक्रम परिचय : भारत में सामाजिक समस्याएँ

सभी पूर्वकालीन समाजों की तरह आधुनिक समाज भी अनेक सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति सामाजिक विकास के एक काल से दूसरे काल में भिन्न होती है। इसी प्रकार, विभिन्न जनजातीय, कृषि एवं औद्योगिक समाजों में संरचना की विभिन्नता के साथ अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएँ पायी जाती है।

इस पाठ्यक्रम में मुख्यतः भारत की सामाजिक समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक बोध एवं भारतीय संदर्भ में इनके विश्लेषण - दोनों बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम में सामाजिक रूपांतरण, संक्रमणकालीन संरचना, वंचन एवं परकीयकरण के रूप, तादात्म्य, गरिमा और सामाजिक न्याय, तथा अंत में पारिस्थितिकी एवं संसाधनों पर चर्चा की गई है।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे देश में सामाजिक समस्याओं का समाजवैज्ञानिक आयामों का पता लगाना है। इससे सामाजिक समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्र की प्रासंगिकता का पता लगाना है। यह पाठ्यक्रम केवल सामाजिक विकृति मूलक ही नहीं है बल्कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्यः (क) समाज और राज्य के बीच संबंधों, (ख) मानव अधिकार, (ग) अंतःस्थ संरचना के संबंध में कल्याणकारी राज्य परिप्रेक्ष्य, और (घ) सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में विगठन का भी पता लगाना है। कुल मिलाकर समग्र रूप से प्रत्येक सामाजिक समस्या पर सामाजिक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है।

इस पाठ्यक्रम को एक दूसरे पर आश्रित सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 में सामान्य और विशेषकर भारत के संदर्भ में सैद्धांतिक मुद्दे और सामाजिक समस्याओं से संबंधित सामाजिक ढाँचे पर चर्चा की गई है। खंड 2 और खंड 3 में सामाजिक जनसांख्यिकी, प्रव्रजन के विन्यास शहरीकरण और पारिवारिक ढाँचे के विशेष संदर्भ सहित भारत में सामाजिक संरचना (संक्रमण) की जाँच परख की है। इन्हीं खंडों में बेरोज़गारी, ग्रामीण उद्योगों की समस्याएँ, महिलाएँ और बाल श्रमिकों के मुद्दों और इनके आपसी संबंधों के बारे में विश्लेषण किया गया है। खंड 4 में वंचन और भेदभाव के ढाँचे तथा इनके गरीबी, अपराध, अपचार, नशीले पदार्थों का सेवन, शराबखोरी, हिंसा और आतंकवाद से होने वाले संबंधों के बारे में दर्शाया गया है। अगले दो खंडों में पहचान और गरिमा तथा अन्य सामाजिक समूहों के सामाजिक न्याय अर्थात् बाल, युवा, महिलाएँ, वृद्ध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा नृजातीय समूहों के बारे में प्रकाश डाला गया है।

हाल ही के वर्षों में पारिस्थितिकी से संबंधित मुददों में वृद्धि हुई है। इस पाठ्यक्रम के अंतिम खंड में इन मुद्दों की सार्थकता के दृष्टिगत भूमि जल (भूजल) और वनों के संबंध में चर्चा की है। इसके साथ ही पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए राज्य और अन्य संगठनों की भूमिका की भी जाँच परख की गई है।